

सकारात्मक. एचआरडी व शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा

उच्च शिक्षा में एससी व एसटी विद्यार्थियों का बढ़ा नामांकन



राजदेव पांडेय पटना

राज्य में हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में इनरोलमेंट बढ़ा है. सामान्य कोटि के छात्र-छात्राओं की तुलना में इन वर्गों के विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा में अधिक रुचि दिखायी है. राज्य में पिछले आठ सालों में उच्च शिक्षा में हुए नामांकन को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है. शिक्षा विभाग इसके पीछे अनुमंडलों

● बाकी पेज 19 पर

बिहार में एसटी का नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक

एससी विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात				एसटी विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात			
शैक्षणिक सत्र	कुल एससी	छात्र	छात्राएं	शैक्षणिक सत्र	कुल एसटी	छात्र	छात्राएं
2018-19	10.0	12.7	7.4	2018-19	18.3	21.9	14.7
2017-18	9.2	11.5	6.9	2017-18	15.1	18.3	11.9
2016-17	9.6	11.9	7.4	2016-17	13.7	16.2	11.2
2015-16	9.3	11.4	7.1	2015-16	12.3	13.4	11.2
2014-15	8.3	10.1	6.5	2014-15	13.4	15.3	11.4
2013-14	8.4	10.2	6.5	2013-14	11.3	13.0	9.6
2012-13	8.5	10.3	6.6	2012-13	14.6	16.0	13.1
2011-12	7.8	9.4	6.1	2011-12	15.0	15.9	14.0

● स्रोत- मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं शिक्षा विभाग बिहार ● सभी आंकड़ें प्रतिशत में



इस साल कुल जीईआर में ज्यादा उत्साहजनक प्रगति नहीं है, लेकिन एससी और एसटी वर्ग के बच्चों का नामांकन अनुपात बेहद सकारात्मक रहा है.

दरअसल सरकार ने एससी और एसटी बहुल क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोले हैं. अगले साल की रिपोर्ट में हमारी प्रगति और शानदार होगी. डॉ रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार

कॉम्फेड को मिला सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी का पुरस्कार



■ दुग्ध उत्पादों के निर्माण, बिक्री में उत्कृष्ट पाये जाने पर मिला सम्मान

फुलवाटीशटीफ. बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन का पुरस्कार दिया गया. एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से नयी दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित भव्य समारोह में कॉम्फेड की प्रबंध निदेशक शिखा श्रीवास्तव को यह पुरस्कार भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी के हाथों द्वारा प्रदान किया गया. अतुल

चतुर्वेदी ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रतीक चिह्न व प्रशस्ति पत्र दिया. बता दें कि इंडिया डेयरी अवार्ड 2020 की ज्यूरी द्वारा कुल 17 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों का वितरण किया गया. इसमें सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी का पुरस्कार बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. (कॉम्फेड) को प्रदान किया गया. कॉम्फेड को यह पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण सुधा दूध उत्पादन तथा सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादों के निर्माण, बिक्री आदि कई आयतों में उत्कृष्ट पाये जाने पर दिया गया है. सुधा ने गत वर्षों में दुग्ध संग्रहण, दुग्ध उत्पादों एवं दूध पाउच मिल्क मार्केटिंग के साथ साथ रिटेल मार्केटिंग में अच्छी वृद्धि दर्ज की है.

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड 143 करोड़ करेगा खर्च, 12 परियोजनाओं पर 10 साल पहले ही काम हुआ था

बिहार की 12 पनबिजली परियोजनाएं अगले साल पूरी होंगी

हिन्दुस्तान

एक्सप्लूजिव

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

वर्षों से बंद पड़ी राज्य की दर्जनभर पनबिजली परियोजनाओं को अगले साल पूरा कर लिया जाएगा। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (बीएचपीसी) इन परियोजनाओं के सिविल वर्क पर काम शुरू कर चुका है। मैकेनिकल वर्क के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। निगम की

कवायद

- सिविल वर्क और मैकेनिकल वर्क कराने में जुटा है निगम
- परियोजना शुरू होने पर 10 मेगावाट बिजली होगी उत्पादित

कोशिश है कि अगले वित्तीय वर्ष में इन सभी परियोजनाओं को चालू कर दिया जाए। इससे राज्य में लगभग 10 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। अधिकारियों के अनुसार निगम के अधीन 12 ऐसी परियोजनाएं थीं जिन पर 10 साल पहले ही काम हुआ था।

अगले वित्तीय वर्ष में 12 पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादन का लक्ष्य है। निगम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
- आलोक कुमार, एमडी, बीएचपीसी

बाद में किन्हीं कारणों से काम बंद हो गया। सरकार ने जब समीक्षा की तो पाया कि इन परियोजनाओं पर लगभग 50 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसलिए वर्षों से बंद पड़ीं इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया। लगभग 145 करोड़ खर्च होने

यहां से होगा उत्पादन

अमेठी, तेजपुर, फहरमा, मथौली, डेहरी स्केप, रामपुर, सिपहा, डेहरा, वालिदाद, बरवल, राजापुर और नटवार।

का आकलन किया गया। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद निगम ने इन परियोजनाओं में सिविल वर्क के लिए पिछले साल ही टेंडर जारी किया था। सिविल वर्क के बाद अब मैकेनिकल वर्क के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि इन

परियोजनाओं पर अनुमान से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। साल 2016-17 में ही इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 145 करोड़ खर्च होने का अनुमान किया गया था, लेकिन काम अब शुरू हुआ है। निगम अधिकारियों ने कहा कि पनबिजली परियोजना के लिए एजेंसियों ने कुछ सामान की आपूर्ति वर्षों पहले की थी। इतने साल काम नहीं होने के कारण अधिकतर बेकार हो चुके हैं। इसलिए सभी परियोजनाओं को पूरा होने में 200 करोड़ तक खर्च हो सकता है।